ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वयं सहायता समूहों (SHG) और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **ग्रामीण क्रेडिट स्कोर (GCS) फ्रेमवर्क** प्रस्तुत किया गया।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर:

- **परिचय:** इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा **ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों की ऋण पात्रता का आकलन करने** तथा ऋण प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
  - इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में **उधारकर्त्ताओं (ऋण प्राप्तकर्त्ता) का अधिक सटीक मूल्यांकन** प्रदान कर **ऋण चुकौती अनुशासन में सुधार लाना** तथा **धोखाधड़ी** को कम करना है।
- **प्रभाव:** यह **माइक्रोफाइनेंस को मज़बूत करेगा**, **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देगा तथा कृषि, ग्रामीण विकास और MSME जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगा।
  - GCS मौजूदा **माइक्रोफाइनेंस मॉडलों** का पूरक होगा तथा ऋणों के मूल्यांकन के लिये CIBIL और CRIF **हाईमार्क जैसे क्रेडिट स्कोर** के साथ मिलकर कार्य करेगा।
  - इस **स्कोर को स्वामित्व योजना** के साथ एकीकृत किया जाएगा।

अन्य पहल:

- **भारतीय डाक का रूपांतरण: केंद्रीय बजट 2025 में भारतीय डाक को 1.5 लाख डाकघरों** और **2.4 लाख डाक सेवकों** के विशाल ग्रामीण नेटवर्क का उपयोग करते हुए एक प्रमुख **सार्वजनिक रसद संगठन** में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के लिये सहायता: सहकारी क्षेत्र** को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिये सहकारी चीनी मिलों को मज़बूत करने के लिये 500 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया गया।

और पढ़ें: केंद्रीय बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, स्वामित्व योजना

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/grameen-credit-score